

श्री गंगी
हताशा में देश की
संवैधानिक संस्थाओं
के खिलाफ बवान दे
रहे हैं। उन्होंने श्री
गंगी की आयोग के
अधिकारियों के
संबंध में 'चुन चुन
कर, देख लूंगा, और उनको छोड़ा नहीं'
जैसी टिप्पणियों पर कहा कि देश के
अधिकारियों को धमकी दिया जाना बहुत
निदनीय है। यह एक तरह से लोकतंत्र पर
आघात है।



संवित पात्रा

राजग ने मोदी, नड़ा को सौंपी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी

11

सेना ने धराली में राहत व बचाव अभियान किया तेज, 70 लोगों को किया रेस्क्यू 12

किसानों-पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं : मोदी

अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति
योजना को मिली मंजूरी

एजेंसी

■

नवी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

व्यापार में भारत के खिलाफ अतिरिक्त

आयात शुल्क लाने के अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले के खिलाफ गुरुवार

को एक कड़ा

और स्पष्ट संदेश देते हुए हुए

कहा कि भारत देश के किसानों, पशुपालकों

और मछुआओं जैसे कमज़ोर वर्ग के लोगों

के हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं

करेगा और वह स्वयं पर सरकार लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा, 'डॉ. स्वामीनाथन ने हमें

सिखाया था कि खेती सिर्फ़ फसल करने की तौर पर भारत रव

स्वार्थी ढंग से एक ऐसे स्वामिनाथन के जर्म

शताब्दी समाजहार के उपलक्ष्य में राजनीति में

कृषि विज्ञान पर एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन

को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा,

'हमारे लिए अपने किसानों का हित

सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने

किसानों के, पशुपालकों के, और मछुआओं

सभी भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी

समझौता नहीं करेगा।' उन्होंने इसी संदर्भ

में कहा, '...और मैं जाता हूं व्यक्तित्व रूप

में कहा, '...और मैं जाता हूं व्यक

कुदरत का कोहराम मा

नासून की दस्तक के साथ ही हिमाचल व उत्तराखण्ड में दरकते पहाड़ व गढ़ रूप दिखाती नदियाँ चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुदरत के कहरे के सामने इसान बैठा ही नजर आता है। तमाम मुख्य नदियाँ उफान पर हैं। जगह-जगह भूखलन से सड़कें ठप पड़ी हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बीच मलबा व पथर गिरने से सैकड़े सड़कें बंद हो गई हैं। सामान्य जनजीवन तुरी तरह प्रभावित है। पहले हम गर्मी से त्रस्त होकर बारिश की आस लगाए होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो स्थितियाँ डराने वाली हो जाती हैं। निसस्दै गलबल बारिश संकट के चलते बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। बारिश कम समय में ज्यादा मात्रा में बरसती है। जिससे न केवल पहाड़ों में कटवां बढ़ जाता है बल्कि पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा गिरकर रस्तों व पानी के प्राकृतिक अवस्थाएँ कर देता है। यह सकट इतनी भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने पहाड़ों को विलसिता का केंद्र बन दिया है। तीर्थांत अब पर्यटन जैसा हो गया है। पर्यटकों के बाहरों से छोटी सड़कें और पुल दबाव में हैं। नीति-नियताओं ने पहाड़ों में सड़कों को फोर लेन-सिक्स लेन बनाने का जो उपक्रम किया है, उससे वारिश का गति तेज हुई है। पहाड़ों के किनारे काटने से भूखलन की गति तेज हुई है। गाह-गाहे पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिरकर यातायात को अवरुद्ध कर देता है। यात्रियों के जीवन पर हर समय संकट बना रहता है। हिमाचल की ही तरह से कुदरत के काहराम से उत्तराखण्ड भी बुरी तरह त्रस्त है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी व पिंडर आदि नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने की घटनाएँ बढ़ने से यात्रा कुछ समय के लिये स्थगित की गई है। बार-बार भारी बारिश को रोड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जगह-जगह सड़कों के कट्टरे से सैकड़े बायाँफोंसे हुए हैं। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। बाल्द फटने की आंशका बाली तापां वाली तरह प्रभावित है। ब्रह्मीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जाने वाली मार्ग जगह-जगह बचाइ है। भारी बारिश की आंशका को देखते हुए स्कूल व आंनाबड़ी केंद्रों में छाटियाँ घोषित की गई हैं। सामान्य जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई मोटरमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हुए हैं। कई छोटे पुल बह गए हैं। कई निचले स्थानों से लोगों को हटाया गया है। कुल मिलाकर लाखों लोगों को अतिवृद्धि ने बंधक बना दिया है। निरचित रूप से तेज बारिश और उसके प्रभाव इसानी नियत्रण से बाहर होता है। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में विकास के मार्गदल पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पहाड़ अध्यात्म के केंद्र भी रहे हैं, उन्हें पर्यटकों की विलसिता को केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अपेक्षित नये हिमालीय पहाड़ों और उसके परिस्थितिकीय तंत्र के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप से ग्लेशियर पिछल रहे हैं और नदियों का बढ़ा जल संकट का कारण भी बन रहा है।

हिमाचल में मूसलाधार बारिश के बीच मलबा व पथर गिरने से सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। पहले हम गर्मी से त्रस्त होकर बारिश की आस लगाए होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो स्थितियाँ डराने वाली हो जाती हैं। निसस्दै गलबल वारिश संकट के चलते बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। बारिश कम समय में ज्यादा मात्रा में बरसती है। जिससे न केवल पहाड़ों में कटवां बढ़ जाता है बल्कि पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा गिरकर रस्तों व पानी के प्राकृतिक अवस्थाएँ कर देता है। यह सकट इतनी भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने पहाड़ों को विलसिता का केंद्र बन दिया है। तीर्थांत अब पर्यटन जैसा हो गया है। पर्यटकों के बाहरों से छोटी सड़कें और पुल दबाव में हैं। नीति-नियताओं ने पहाड़ों में सड़कों को फोर लेन-सिक्स लेन बनाने का जो उपक्रम किया है, उससे वारिश का गति तेज हुई है। पहाड़ों के किनारे काटने से भूखलन की गति तेज हुई है। गाह-गाहे पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिरकर यातायात को अवरुद्ध कर देता है। यात्रियों के जीवन पर हर समय संकट बना रहता है। हिमाचल की ही तरह से कुदरत के काहराम के बाहर में उत्तराखण्ड भी बुरी तरह त्रस्त है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी व पिंडर आदि नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर मलबा गिरने की घटनाएँ बढ़ने से यात्रा कुछ समय के लिये स्थगित की गई है। बार-बार भारी बारिश को रोड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जगह-जगह सड़कों के कट्टरे से सैकड़े बायाँफोंसे हुए हैं। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। बाल्द फटने की आंशका बाली तापां वाली से छोटी सड़कों के कट्टरे से सैकड़े बायाँफोंसे हुए हैं। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। कई छोटे पुल बह गए हैं। कई निचले स्थानों से लोगों को हटाया गया है। कुल मिलाकर लाखों लोगों को अतिवृद्धि ने बंधक बना दिया है। निरचित रूप से तेज बारिश और उसके प्रभाव इसानी नियत्रण से बाहर होता है। लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी इलाकों में विकास के मार्गदल पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। पहाड़ अध्यात्म के केंद्र भी रहे हैं, उन्हें पर्यटकों की विलसिता को केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अपेक्षित नये हिमालीय पहाड़ों और उसके परिस्थितिकीय तंत्र के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप से ग्लेशियर पिछल रहे हैं और नदियों का बढ़ा जल संकट का कारण भी बन रहा है।

संसद संवाद की बजाय संघर्ष का अखाड़ा कब तक?

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में गतिरोध जारी है, जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। आज संसद का दृश्य सार्थक संवाद की बजाय किसी अखाड़े से कम नहीं लगता। बहस के स्थान पर बैनर, तख्तियाँ और नारों की गंज सुनाई देती है। संसद जहां नीति निर्णय होना चाहिए, वहां प्रतिदिन कार्यवाही स्थगित हो रही है। यह विंडबना है कि जनप्रियतिहीन जिन मुद्दों को लेकर चुने जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की बजाय वे मर्जिं थथपाने, बैल और उत्तरन और मारक बंद करने में लगे हैं। संसद का द्वागमा के बावजूद विदेशी दिव्यांशुओं में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में बहस के बाजाय बहिष्कार और गतिरोध होती है। मानसून सत्र की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, नए विधेयकों, जनहित की बहसों और लोकतांत्रिक विधेयों की। लेकिन यह सत्र भी पुराने दौरे पर चल पड़ा, विरोध, स्थान, नारेबाजी और हंगामे की भैंट द्वारा लोकतंत्र लोकतंत्र। विपक्ष बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे गंभीर मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की दृष्टि, बैटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चाहती है। इसके बावजूद विदेशी दिव्यांशुओं में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे गंभीर मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की दृष्टि, बैटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चाहती है। इसके बावजूद विदेशी दिव्यांशुओं में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे गंभीर मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की दृष्टि, बैटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चाहती है। इसके बावजूद विदेशी दिव्यांशुओं में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे गंभीर मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की दृष्टि, बैटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चाहती है। इसके बावजूद विदेशी दिव्यांशुओं में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं

